



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 234]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 5, 2010/वैशाख 15, 1932

No. 234]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 5, 2010/VAISAKHA 15, 1932

गृह मंत्रालय

(सी एस प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मई, 2010

सा.का.नि. 381(अ).—कैदी सम्प्रत्यावर्तन अधिनियम, 2003 (2003 का 49) की धारा 3 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्वारा, निदेश देती है कि उक्त अधिनियम के उपबंध कोरिया गणराज्य की सरकार के लिए लागू होंगे तथा भारत गणराज्य की सरकार और कोरिया गणराज्य की सरकार के बीच हुई संधि के पाठ को निम्न प्रकार अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

“दण्डित व्यक्तियों के अन्तरण के संबंध में भारत-गणराज्य सरकार तथा कोरिया लोक-गणराज्य की सरकार के बीच करार”

भारत-गणराज्य की सरकार तथा कोरिया लोक-गणराज्य की सरकार, जिन्हें इसमें इसके बाद संविदाकार देश कहा गया है;

दण्डित व्यक्तियों का उनके स्वयं के देशों में सामाजिक पुनर्वास सुगम बनाने की अभिलाषा से; और

यह मानते हुए कि यह उद्देश्य, कोई अपराध करने के परिणामस्वरूप दोषसिद्ध और दंडित किए गए विदेशी नागरिकों को उनके स्वयं के समाज में अपनी सज़ा काटने का अवसर प्रदान करके पूरा किया जाना चाहिए;

निम्न प्रकार सहमत हो गई हैं :

अनुच्छेद 1

परिभाषा

- (क): “निर्णय” से तात्पर्य न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के किसी ऐसे निर्णय अथवा आदेश से है जिसके तहत दण्ड दिया गया हो;
- (ख): “प्राप्तकर्ता देश” से तात्पर्य उस देश से है जिसको दण्डित व्यक्ति सज़ा काटने के प्रयोजन से अंतरित किया जा सकता हो अथवा अंतरित किया गया हो;
- (ग): “दण्ड” से तात्पर्य किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण द्वारा अपने दंडिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए निर्धारित समयावधि के लिए या आजीवन के लिए आजादी से वंचित रखे जाने का कोई दंड या उपाय है;
- (घ): “दण्डित व्यक्ति” से तात्पर्य किसी न्यायालय, जिसमें संविदाकार देश में तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा स्थापित न्यायालय भी शामिल हैं, द्वारा पारित किसी आदेश के तहत कारावास की सज़ा काट रहे व्यक्ति से है;
- (ङ): “अंतरणकर्ता देश” से तात्पर्य उस देश से है जिसमें उस व्यक्ति को दंड दिया गया हो जिसे अंतरित किया जा सकता हो या जिसे अंतरित कर दिया गया हो।

अनुच्छेद 2

सामान्य सिद्धांत

- (1). इस करार के प्रावधानों के अनुसार कोई संविदाकार देश के भू-भाग में दंडित किसी व्यक्ति को सज़ा काटने के लिए दूसरे संविदाकार देश के भू-भाग में अंतरित किया जा सकता है ताकि वह उसे दी गई सज़ा काट सके। इस संबंध में दंडित व्यक्ति इस करार के अंतर्गत अन्तरणकर्ता देश अथवा प्राप्तकर्ता देश से ऐसे अंतरण के लिए अपनी इच्छा व्यक्त कर सकता है।
- (2). दंडित व्यक्ति से अन्तरण संबंधी ऐसी इच्छा के प्राप्त होने पर, कोई भी संविदाकार देश दूसरे देश से दंडित व्यक्ति के अन्तरण का अनुरोध कर सकता है।

अनुच्छेद 3अंतरण की शर्तें

(1). इस करार के अंतर्गत किसी दंडित व्यक्ति को निम्नलिखित शर्तों पर ही अन्तरित किया जा सकता है :

- (क): वह व्यक्ति प्राप्तकर्ता देश का नागरिक हो;
- (ख): दंडित व्यक्ति को मृत्युदण्ड नहीं दिया गया हो;
- (ग): निर्णय अंतिम हो;
- (घ): दण्ड के साथ-साथ कोई अन्य शास्ति जिनमें जुर्माना भी शामिल है का पालन किया जाए;
- (ङ): अन्तरणकर्ता देश में दंडित व्यक्ति के विरुद्ध कोई जांच, विचारण अथवा किसी अन्य प्रकार की दांडिक कार्रवाई लम्बित नहीं हो;
- (च): अंतरण के अनुरोध की प्राप्ति के समय दंडित व्यक्ति द्वारा भोगी जाने वाली शेष सज़ा की अवधि कम से कम छः माह बची हो अथवा वह आजीवन कारावास की सज़ा काट रहा हो;
- (छ): कि व्यक्ति को अंतरणकर्ता देश में जिस कृत्य अथवा गलती के लिए दंड दिया गया था, वह प्राप्तकर्ता देश में दांडिक अपराध हो;
- (ज): दंडित व्यक्ति को सैन्य कानून के तहत दंडित न किया गया हो;
- (झ): प्राप्तकर्ता देश में दंडित व्यक्ति की हिरासत को अंतरित करने से अंतरणकर्ता देश की संप्रभुता, सुरक्षा अथवा किसी अन्य हित पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ता हो;
- (ञ): अंतरण के संबंध में दंडित व्यक्ति द्वारा सहमति दी जाती है अथवा किसी भी संविदाकार देश द्वारा दंडित व्यक्ति की आयु अथवा शारीरिक या मानसिक स्थिति को ध्यान में रखकर जरूरी समझे जाने पर अंतरणकर्ता देश के कानून के अनुसरण में उस व्यक्ति की ओर से कार्य करने के लिए हकदार किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सहमति दी गई हो; और
- (ट): अंतरणकर्ता और प्राप्तकर्ता देश अंतरण के संबंध में सहमत हों।

(2). आपवादिक मामलों में, यदि दंडित व्यक्ति द्वारा भोगे जा रहे दंड की शेष अवधि छः माह से कम हो तो भी अंतरणकर्ता और प्राप्तकर्ता देश अंतरण के संबंध में सहमत हो सकते हैं।

अनुच्छेद 4

सूचना भेजने का दायित्व

(1). यदि दंडित व्यक्ति ने अन्तरणकर्ता देश को इस करार के तहत अन्तरित होने की इच्छा व्यक्त की हो तो अंतरणकर्ता देश प्राप्तकर्ता देश को निम्नलिखित सूचना तथा दस्तावेज भेजेगा बशर्ते कि प्राप्तकर्ता या अन्तरणकर्ता देश में से किसी के भी द्वारा पहले ऐसा कोई निर्णय न लिया गया हो कि वह अन्तरण के लिए सहमत नहीं है :

- (क): दंडित व्यक्ति का नाम और राष्ट्रीयता, जन्म तिथि एवं जन्म स्थान;
- (ख): प्राप्तकर्ता देश में उसका पता, यदि कोई हो;
- (ग): उन तथ्यों का विवरण जिन पर दंड आधारित था;
- (घ): दंड की प्रकृति, समयावधि एवं प्रारंभ होने की तारीख;
- (ङ): निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा कानून के उन संगत उपबंधों की एक प्रति जिनके अंतर्गत दंडित व्यक्ति के खिलाफ दंड पारित किया गया;
- (च): दंडित व्यक्ति की कोई डाक्टरी, सामाजिक अथवा अन्य कोई रिपोर्ट, जहां वह उसके आवेदन के निपटान अथवा उसकी परिरुद्धता की प्रकृति के निर्णय के लिए प्रासंगिक हो;
- (छ): कोई अन्य जानकारी जिसके लिए प्राप्तकर्ता देश यह विनिर्दिष्ट करे कि यह संबंधित मामले में अंतरण की संभावना पर विचार करने के लिए जरूरी है और जिससे वह अपने कानून के अंतर्गत दंडित व्यक्ति को अंतरण के सम्पूर्ण परिणामों की जानकारी देने में सक्षम हो सके;
- (ज): अंतरित किए जाने वाले दंडित व्यक्ति अथवा अंतरणकर्ता देश के कानून के अनुसरण में उसकी ओर से कार्य करने के लिए किसी भी व्यक्ति की इच्छा की अभिव्यक्ति;

(झ): किसी विचारण पूर्व नजरबंदी, क्षमा या दंड प्रवर्तन के लिए संगत किसी अन्य तथ्य को शामिल करते हुए एक विवरण पत्र जिसमें यह उल्लेख किया गया हो कि कितना दंड पूरा हो चुका है।

(2). इस करार के अधीन किसी अनुरोध पर कोई भी निर्णय लिए जाने के प्रयोजन से प्राप्तकर्ता देश अंतरणकर्ता देश को निम्नलिखित जानकारी एवं दस्तावेज तभी भेजेगा बशर्ते कि प्राप्तकर्ता या अंतरणकर्ता देश ने पहले ही यह निश्चय कर लिया हो कि वह अंतरण से सहमत नहीं है :

(क): एक विवरण अथवा दस्तावेज जो यह दर्शाता हो कि दंडित व्यक्ति प्राप्तकर्ता देश का एक नागरिक है;

(ख): प्राप्तकर्ता देश के संगत कानून की एक प्रति जिसमें ऐसे कृत्यों अथवा चूकें, जिनके कारण अंतरणकर्ता देश में दण्ड पारित किया गया है, वे प्राप्तकर्ता देश के कानून के अंतर्गत अपराध माने गए हों अथवा यदि, ऐसे कृत्य अथवा चूकें इसके भू-भाग में घटित हों, तो उसे अपराध माना जाएगा;

(ग): दंडित व्यक्ति के अन्तरण पर इस करार के अनुच्छेद 8 के पैराग्राफ 2 के प्रभाव का विवरण, यदि लागू हो, के सहित उसके अन्तरण के बाद प्राप्तकर्ता देश में सजा की अवधि एवं प्रवर्तन संबंधी किसी कानून अथवा विनियम के प्रभाव का विवरण;

(घ): दण्डित व्यक्ति के अंतरण को स्वीकार करने के लिए प्राप्तकर्ता देश की सहमति और दंडित व्यक्ति की सजा के बाकी बचे हिस्से को शासित करने हेतु एक वचनबद्धता; तथा

(ङ): कोई अन्य सूचना अथवा दस्तावेज जिसे अंतरणकर्ता देश आवश्यक समझे।

(3). यदि, दण्डित व्यक्ति ने अंतरण के लिए प्राप्तकर्ता देश के प्रति अपनी इच्छा अभिव्यक्त की है तो, प्राप्तकर्ता देश, तदनुसार, इसकी सूचना अंतरणकर्ता देश को देगा, जो उस पर अनुच्छेद 4 (1) के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करेगा।

1697 G/102.

अनुच्छेद 5

अनुरोध एवं जवाब

- (1). अंतरण के लिए अनुरोध लिखित रूप में, निर्धारित प्रपत्र, यदि कोई हो, में प्रस्तुत किया जाएगा और राजनयिक माध्यम के द्वारा अनुरोधकर्ता-देश के केन्द्रीय प्राधिकारी के माध्यम से प्रार्थित देश के केन्द्रीय प्राधिकारी को सम्बोधित किया जाएगा। जवाब उसी माध्यम से सूचित किए जाएंगे।
- (2). इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 के प्रयोजन हेतु, भारत-गणराज्य के संबंध में गृह मंत्रालय और कोरिया-गणराज्य के संबंध में न्याय मंत्रालय, केन्द्रीय प्राधिकारी होंगे।
- (3). प्रार्थित देश शीघ्रतापूर्वक अनुरोधकर्ता देश को अपने निर्णय के बारे में सूचित करेगा कि वह प्रार्थित अंतरण के लिए सहमत है अथवा नहीं।

अनुच्छेद 6

सहमति और इसका सत्यापन

- (1). अंतरणकर्ता देश यह सुनिश्चित करेगा कि इस करार के अनुच्छेद 3 के पैराग्राफ 1 (i) के अनुसार अंतरण के लिए सहमति देने वाला व्यक्ति, ऐसा स्वेच्छा से तथा इसके कानूनी परिणामों की पूरी जानकारी के साथ कर रहा है। इस प्रकार की सहमति देने की प्रक्रिया को अंतरणकर्ता देश के कानून द्वारा शासित किया जाएगा।
- (2). अंतरणकर्ता देश, प्राप्तकर्ता देश को यह सत्यापित करने के लिए एक अवसर प्रदान करेगा कि सहमति, इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 में दी गई शर्तों के अनुसार दी गई है।

अनुच्छेद 7

प्राप्तकर्ता देश के लिए अंतरण का प्रभाव

- (1). प्राप्तकर्ता देश के सक्षम प्राधिकारी, न्यायालय अथवा प्रशासनिक आदेश, जैसा भी इसके राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत अपेक्षित हो, के माध्यम से इस करार के अनुच्छेद 8 में दी गई शर्तों के अंतर्गत सजा के प्रवर्तन को जारी रखेंगे।

(2). इस करार के अनुच्छेद 10 के प्रावधानों के अध्यधीन, सज़ा का प्रवर्तन प्राप्तकर्ता देश के कानून द्वारा शासित किया जाएगा और सिर्फ वही देश समस्त समुचित निर्णय लेने के लिए सक्षम होगा।

अनुच्छेद 8

सज़ा का सतत प्रवर्तन

(1). प्राप्तकर्ता देश, अंतरणकर्ता देश द्वारा यथा-अभिनिर्धारित सज़ा की कानूनी प्रकृति एवं अवधि द्वारा आबद्ध होगा।

(2). तथापि, यदि सज़ा की प्रकृति अथवा अवधि अथवा दोनों ही प्राप्तकर्ता देश के कानून से असंगत हों, अथवा इसके कानून में ऐसा अपेक्षित हो, तो प्राप्तकर्ता देश न्यायालय अथवा प्रशासनिक आदेश द्वारा सज़ा को अपने स्वयं के कानून द्वारा निर्धारित दण्ड अथवा उपाय में रूपान्तरित कर सकेगा। जहां तक इसकी प्रकृति एवं अवधि का प्रश्न है, रूपान्तरित दण्ड अथवा उपाय, यथासंभव, अंतरणकर्ता देश के अधिनिर्णय द्वारा आरोपित सज़ा के अनुरूप होगा। तथापि, यह अपनी प्रकृति अथवा अवधि द्वारा अंतरण देश में आरोपित की गई सज़ा में वृद्धि नहीं करेगा।

अनुच्छेद 9

अंतरणकर्ता देश के लिए सज़ा के अंतरण/समापन का प्रभाव

(1). प्राप्तकर्ता देश के प्राधिकारियों द्वारा दण्डित व्यक्ति का प्रभार ग्रहण, अंतरणकर्ता देश में प्राधिकारियों द्वारा दी गई सज़ा के प्रवर्तन के समापन पर प्रभावी होगा।

(2). यदि, प्राप्तकर्ता देश समझता है कि सज़ा का प्रवर्तन समाप्त हो चुका है, तो अंतरणकर्ता देश सज़ा प्रवृत्त नहीं करेगा।

(3). जब प्राप्तकर्ता देश इस करार के अनुच्छेद 12 के पैराग्राफ 1 (क) के तहत अंतरणकर्ता देश को यह अधिसूचित करता है कि दंड पूरा हो गया है तो वह दंड अंतरणकर्ता देश में प्रवर्तनीय नहीं रहेगा।

अनुच्छेद 10माफी, राजक्षमा अथवा लघुकरण और निर्णय की समीक्षा

- (1). केवल अंतरणकर्ता देश ही निर्णय की पुनरीक्षा के लिए किसी आवेदन-पत्र पर निर्णय लेगा।
- (2). कोई भी संविदाकार देश अपने संविधान अथवा अन्य कानूनों के अनुरूप दंड की माफी, राजक्षमा प्रदान कर सकेगा अथवा दण्ड का लघुकरण कर सकेगा।

अनुच्छेद 11दण्ड के प्रवर्तन की समाप्ति

जैसे ही अंतरणकर्ता देश द्वारा किसी भी ऐसे फैसले अथवा उपाय की सूचना दी जाती है, जिसके परिणामस्वरूप दंड को कम अथवा उसका प्रवर्तन समाप्त किया गया हो, तो प्राप्तकर्ता देश दंड को आशोधित अथवा उसके प्रवर्तन को समाप्त कर देगा।

अनुच्छेद 12दण्ड के प्रवर्तन संबंधी सूचना

- (1). प्राप्तकर्ता देश अंतरणकर्ता देश को अधिसूचित करेगा :
 - (क): जब दण्ड का प्रवर्तन पूरा कर लिया गया हो; अथवा
 - (ख): यदि दण्ड का प्रवर्तन पूरा होने से पहले दंडित व्यक्ति हिरासत से भाग जाता है। ऐसे मामलों में प्राप्तकर्ता देश को चाहिए कि वह दंडित व्यक्ति की गिरफ्तारी का हर-संभव प्रयास करे ताकि वह स्वयं को मिले दण्ड का शेष भाग पूरा कर सके और कैदी पर, कैदी के भाग निकलने पर प्राप्तकर्ता देश के संगत कानून के अन्तर्गत किए गए अपराध के लिए अभियोग चलाया जा सके।
- (2). यदि अंतरणकर्ता देश द्वारा अपेक्षित हो तो प्राप्तकर्ता देश दंड के प्रवर्तन के संबंध में एक विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

अनुच्छेद 13

अभिवहन

यदि कोई भी संविदाकार देश दंडित व्यक्तियों के अंतरण के लिए किसी तीसरे देश के साथ कोई व्यवस्था करता है तो दूसरा संविदाकार देश ऐसी व्यवस्था के अनुसरण में अपने भू-भाग से अंतरित किए जाने वाले दंडित व्यक्तियों के अभिवहन को सुकर बनाने में सहयोग करेगा सिवाय इसके कि वह किसी ऐसे दंडित व्यक्ति के अभिवहन से इन्कार करे जो वहीं का राष्ट्रिक हो। ऐसे अंतरण का इच्छुक संविदाकार देश दूसरे संविदाकार देश को ऐसे अभिवहन के बारे में अग्रिम नोटिस देगा।

अनुच्छेद 14

दंडित व्यक्तियों का सौंपा जाना

अंतरणकर्ता देश के प्राधिकारी प्राप्तकर्ता देश के प्राधिकारियों को दोनों देशों की सहमति के अनुसार, अंतरणकर्ता देश के क्षेत्राधिकार के भीतर निर्धारित तारीख, समय तथा स्थान पर दंडित व्यक्ति को सौंपेगा।

अनुच्छेद 15

लागत

अंतरणकर्ता देश के अनन्य भू-भाग में होने वाले व्ययों को छोड़कर, इस करार को लागू करने में आने वाले सभी व्यय प्राप्तकर्ता देश द्वारा वहन किए जाएंगे। तथापि, प्राप्तकर्ता देश अंतरण में होने वाले व्यय की सम्पूर्ण अथवा आंशिक वसूली दंडित व्यक्ति अथवा किसी अन्य संसाधन से कर सकता है।

अनुच्छेद 16

भाषा

अनुरोध एवं सहायक दस्तावेज अंग्रेजी में होंगे अथवा उसके साथ अंग्रेजी अनुवाद लगा हो या अन्य संविदाकार देश की राजभाषा का अनुवाद संलग्न होगा।

16976/16-3.

अनुच्छेद 17

विवादों का निपटान

यदि केन्द्रीय प्राधिकारी इस संधि की व्याख्या, इसे लागू करने अथवा इसके कार्यान्वयन से उत्पन्न किसी विवाद पर स्वयं किसी सहमति पर पहुंचने पर विफल रहते हैं तो इसका निपटान राजनयिक चैनलों के माध्यम से होगा।

अनुच्छेद 18

लागू होने का दायरा

यह करार इसके प्रभावी होने की तारीख से पहले या बाद में लगाए गए दण्ड के प्रवर्तन पर लागू होगा।

अनुच्छेद 19

संशोधन

संविदाकार देशों द्वारा सहमत इस करार में कोई संशोधन अथवा आशोधन तभी प्रभावी होगा जब इसकी राजनयिक टिप्पणियों के आदान-प्रदान द्वारा पुष्टि कर दी जाए।

अनुच्छेद 20

अंतिम प्रावधान

- (1). यह करार, अनुसमर्थन के अध्यधीन होगा तथा अनुसमर्थन के लिखत का आदान-प्रदान करने की तारीख से प्रभावी होगा।
- (2). यह करार, किसी भी संविदाकार देश द्वारा दूसरे संविदाकार देश को करार के परिसमापन के अपने आशय की लिखित सूचना दिए जाने की तारीख से छह माह तक प्रभावी रहेगा।
- (3). किसी भी परिसमापन के बावजूद यह करार उन दंडित व्यक्ति के दंडों के प्रवर्तन पर लागू रहेगा जिसे इस परिसमापन के लागू होने की तारीख से पहले इस करार के अंतर्गत अंतरित किया गया हो।

इस करार के साक्ष्य के रूप में अपनी-अपनी सरकारों द्वारा इस संबंध में उचित प्रकार से प्राधिकृत किए जाने पर अधोहस्ताक्षरी ने इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

इसे दिनांक 25 जनवरी, 2010 को हिन्दी, कोरियन और अंग्रेजी भाषा की दो प्रतियाँ में तैयार किया गया है। इसके सभी पाठ समान रूप से अधिप्रमाणित होने पर भी, व्याख्या में मतभेद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

भारत-गणराज्य की सरकार की ओर से

कोरिया गणतंत्र की सरकार की ओर से

ह./-

(एस. एम. कृष्णा)

विदेश मंत्री

ह./-

(यू म्युंग-हान)

विदेश एवं व्यापार मंत्री

[फा. सं. 17011/9/2007-पी.आर.]

डॉ. निर्मलजीत सिंह कलसी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(CS Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th May, 2010

G.S.R. 381(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 3 of the Repatriation of Prisoners Act, 2003 (49 of 2003), the Central Government hereby directs that the provisions of the said Act shall apply to the Government of Republic of Korea and notifies the text of the treaty entered into between the Government of the Republic of India and the Government of Republic of Korea as follows, namely:-

“AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF REPUBLIC OF INDIA AND THE GOVERNMENT OF REPUBLIC OF KOREA ON THE TRANSFER OF SENTENCED PERSONS”

The Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Korea hereinafter referred to as the Contracting States;

Desiring to facilitate the social rehabilitation of sentenced persons into their own countries; and

Considering that this objective should be fulfilled by giving foreigners, who have been convicted and sentenced as a result of their commission of a criminal offence, the opportunity to serve their sentences within their own society;

Have agreed as follows:

ARTICLE 1 DEFINITIONS

- (a): "judgment" means a decision or order of a court or tribunal imposing a sentence;
- (b): "receiving State" means a State to which the sentenced person may be, or has been, transferred in order to serve his sentence;
- (c) : "sentence" means any punishment or measure involving deprivation of liberty ordered by a court or tribunal for a determinate period of time or for life imprisonment, in the exercise of its criminal jurisdiction;
- (d): "sentenced person" means a person undergoing a sentence of imprisonment under an order passed by a court including the courts established under the law for the time being in force in the Contracting States;
- (e): "transferring State" means the State in which the sentence was imposed on the person who may be, or has been transferred.

ARTICLE 2 GENERAL PRINCIPLES

1. A person sentenced in the territory of one Contracting State may be transferred to the territory of the other Contracting State in accordance with the provisions of this Agreement in order to serve the sentence imposed on him. To that end, he may express to the transferring State or the receiving State his willingness to be transferred under this Agreement.
2. The transfer of sentenced person may be requested by either of the Contracting states to the other, on receipt of such expression of willingness for transfer from the sentenced person.

ARTICLE 3 CONDITIONS FOR TRANSFER

1. A sentenced person may be transferred under this Agreement only on the following conditions:
 - (a): the person is a national of the receiving State;
 - (b): the death penalty has not been imposed on the sentenced person;
 - (c): the judgment is final;
 - (d): any accompanying penalties including fine have been complied with ;
 - (e): no inquiry, trial or any other criminal proceeding is pending against the sentenced person in the transferring State;
 - (f): at the time of receipt of the request for transfer, the sentenced person still has at least six months of the sentence to serve or is undergoing a sentence of life imprisonment;
 - (g): that the acts or omissions for which that person was sentenced in the transferring State are those which would constitute a criminal offence in the receiving State,

(h): the sentenced person has not been convicted for an offence under the military law;

(i): transfer of custody of the sentenced person to the receiving State shall not be prejudicial to the sovereignty, security or any other interest of the transferring State;

(j): consent to the transfer is given by the sentenced person or, where in view of his age or physical or mental condition either Contracting State considers it necessary, by any other person entitled to act on his behalf, in writing, in accordance with the law of the Contracting State; and

(k) the transferring and receiving States agree to the transfer.

2. In exceptional cases, the transferring and receiving States may agree to a transfer even if the remaining period to be served by the sentenced person is less than six months

ARTICLE 4 OBLIGATION TO FURNISH INFORMATION

1. If the sentenced person has expressed an interest to the transferring State in being transferred under this Agreement, the transferring State shall send the following information and documents to the receiving State unless either the receiving or the transferring State has already decided that it will not agree to the transfer:

(a): the name and nationality, date and place of birth of the sentenced person;

(b): his address, if any, in the receiving State;

(c): a statement of the facts upon which the sentence was based;

(d): the nature, duration and date of commencement of the sentence;

(e): a certified copy of the judgment and a copy of the relevant provisions of the law under which the sentence has been passed against the sentenced person;

(f): a medical, social or any other report on the sentenced person, where it is relevant for the disposal of his application or for deciding the nature of his confinement;

(g): any other information which the receiving State may specify as required in all cases to enable it to consider the possibility of transfer and to enable it to inform the sentenced person of the full consequences of transfer for him under its law;

(h): the expression of interest of the sentenced person to be transferred or of a person entitled to act on his behalf in accordance with the law of the transferring State; and

(i): a statement indicating how much of the sentence has already been served, including information on any pre-trial detention, remission, or any other factor relevant to the enforcement of the sentence.

2. For the purposes of enabling a decision to be made on a request under this Agreement, the receiving State shall send the following information and documents to the transferring State unless either the receiving or the transferring State has already decided that it will not agree to the transfer:

169791/10-4

- (a): a statement or document indicating that the sentenced person is a national of the receiving State;
 - (b): a copy of the relevant law of the receiving State constituting the acts or omissions, on account of which the sentence has been passed in the transferring State, as if such acts or omissions were an offence under the law of the receiving State or would constitute an offence if committed on its territory;
 - (c): a statement of the effect of any law or regulation relating to the duration and enforcement of the sentence in the receiving State after the sentenced person's transfer including, if applicable, a statement of the effect of paragraph 2 of Article 8 of this Agreement on his transfer;
 - (d): the willingness of the receiving State to accept the transfer of the sentenced person and an undertaking to administer the remaining part of the sentence of the sentenced person; and
 - (e): any other information or document which the transferring State may consider necessary.
3. In case the sentenced person has expressed an interest for transfer to the receiving State, it shall inform the transferring state accordingly, which shall thereon act in accordance with the provisions of Article 4(1)

ARTICLE 5 REQUESTS AND REPLIES

1. Requests for transfer shall be made in writing in the prescribed proforma, if any, and addressed through the central authority of the requesting State through diplomatic channels to the central authority of the requested State. Replies shall be communicated through the same channels.
2. For the purpose of paragraph 1 of this Article, the central authority shall be, in relation to Republic of India, the Ministry of Home Affairs; and in relation to the Republic of Korea, the Ministry of Justice.
3. The requested State shall promptly inform the requesting State of its decision whether or not to agree to the requested transfer.

ARTICLE 6 CONSENT & ITS VERIFICATION

1. The transferring State shall ensure that the person required to give consent to the transfer in accordance with paragraph 1(i) of Article 3 of this Agreement, does so voluntarily and with full knowledge of the legal consequences thereof. The procedure for giving such consent shall be governed by the law of the transferring State.
2. The transferring State shall afford an opportunity to the receiving State to verify that the consent is given in accordance with the conditions set out in paragraph 1 of this Article.

ARTICLE 7
EFFECT OF TRANSFER FOR THE RECEIVING STATE

1. The competent authorities of the receiving State shall continue the enforcement of the sentence through a court or administrative order, as may be required under its national law, under the conditions set out in Article 8 of this Agreement.
2. Subject to the provisions of Article 10 of this Agreement, the enforcement of the sentence shall be governed by the law of the receiving State and that State alone shall be competent to take all appropriate decisions.

ARTICLE 8
CONTINUED ENFORCEMENT OF SENTENCE

1. The receiving State shall be bound by the legal nature and duration of the sentence as determined by the transferring State.
2. If, however, the sentence is by its nature or duration or both incompatible with the law of the receiving State, or its law so requires, that State may, by court or administrative order, adapt the sentence to a punishment or measure prescribed by its own law. As to its nature and duration, the punishment or measure shall, as far as possible, correspond with that imposed by the judgment of the transferring State. It shall however not aggravate, by its nature or duration, the sentence imposed in the transferring State.

ARTICLE 9
**EFFECT OF TRANSFER/COMPLETION OF SENTENCE FOR
TRANSFERRING STATE**

1. The taking into charge of the sentenced person by the authorities of the Receiving State shall have the effect of discontinuing the enforcement of the sentence by the authorities in the Transferring State.
2. The Transferring State shall not enforce the sentence if the Receiving State considers enforcement of the sentence to have been completed.
3. When the receiving State notifies the transferring State under paragraph 1(a) of Article 12 of this Agreement that the sentence has been completed, such notification shall have the effect of discharging that sentence in the transferring State.

1697 G/110-5

ARTICLE 10**PARDON, AMNESTY OR COMMUTATION AND REVIEW OF JUDGMENT**

1. The transferring State alone shall decide on any application for the review of the judgment.
2. Either of the Contracting States may grant pardon, amnesty or commutation of the sentence in accordance with its Constitution or other laws.

ARTICLE 11**TERMINATION OF ENFORCEMENT OF SENTENCE**

The receiving State shall modify or terminate enforcement of the sentence as soon as it is informed by the transferring State of any decision or measure as a result of which the sentence is reduced or ceases to be enforceable.

ARTICLE 12**INFORMATION ON ENFORCEMENT OF SENTENCE**

1. The receiving State shall notify the transferring State :
 - (a): when the enforcement of the sentence has been completed; or
 - (b): if the prisoner escapes from custody before enforcement of the sentence has been completed. In such cases, the receiving State shall make every effort to have the prisoner arrested so that he serves the remainder of his sentence and that the prisoner be prosecuted for committing an offence under the relevant law of the receiving State on escape of prisoner.
2. The receiving State shall furnish a special report concerning the enforcement of the sentence, if so required by the transferring State.

ARTICLE 13**TRANSIT**

If either Contracting State enters into arrangements for the transfer of sentenced persons with any third State, the other Contracting State, shall cooperate in facilitating the transit through its territory of the sentenced persons being transferred pursuant to such arrangements, except that it may refuse to grant transit to any sentenced person who is one of its own nationals. The Contracting State intending to make such a transfer shall give advance notice to the other Contracting State of such transit.

ARTICLE 14

HANDING OVER OF SENTENCED PERSON

Delivery of the sentenced person by the authorities of the transferring State to those of the receiving State shall occur on a date, time and at a place within the jurisdiction of the transferring State as may be agreed upon by both the States.

ARTICLE 15

COSTS

Any costs incurred in the application of this Agreement shall be borne by the receiving State, except costs incurred exclusively in the territory of the transferring State. The receiving State may, however, seek to recover all or part of the costs of transfer from the sentenced person or from some other source.

ARTICLE 16

LANGUAGE

Requests and supporting documents shall be in English or shall be accompanied by a translation into English or the official language of the other Contracting State.

ARTICLE 17

SETTLEMENT OF DISPUTES

Any dispute arising out of the interpretation, application, or implementation of this Agreement shall be resolved through diplomatic channels if the Central Authorities are themselves unable to reach agreement.

ARTICLE 18

SCOPE OF APPLICATION

This Agreement shall be applicable to the enforcement of sentences imposed either before or after the entry into force of this Agreement.

ARTICLE 19

AMENDMENTS

Any amendments or modifications to this Agreement agreed by the Contracting States shall come into effect when confirmed by an exchange of diplomatic notes.

ARTICLE 20
FINAL PROVISIONS

1. This Agreement shall be subject to ratification and shall enter into force on the date on which instruments of ratification are exchanged.
2. The Agreement shall continue to remain in force until six months from the date upon which either Contracting State gives written notice to the other Contracting State of its intention to terminate it.
3. Notwithstanding any termination, this Agreement shall continue to apply to the enforcement of sentences of sentenced persons who have been transferred under this Agreement before the date on which such termination takes effect.

In witness whereof the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done in duplicate at New Delhi on the 25th day of January, 2010, in the Hindi, Korean and English languages, all texts being equally authentic. In case of differences in interpretation, the English text shall prevail.

**For the Government of the
Republic of India**

**For the Government of the
Republic of Korea**

Sd/-

Sd/-

(S.M. Krishna)

(Yu Myung-hwan)

Minister of External Affairs Minister of Foreign Affairs and Trade.”.

[F. No. 17011/9/2007-PR]

Dr. NIRMALJEET SINGH KALSI, Jt. Secy.